12.25 hrs.

ESTATE DUTY (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S. M. KRISHNA): Sir. on behalf of Shri Pranab Kumar Mukherjee I beg for leave to introduce a Bill further to amend the Estate Duty Act, 1953.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Estate Duty Act, 1953."

The motion was adopted.

SHRI S. M. KRISHNA : Sir I introduce** the Bill.

12.26 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

 Need to Constitute a Committee of arctitectural expents to save Taj Mahal from Pollution and damage.

श्री राजेज कुमार सिंह (फिरोजाबाद): कुछ सप्ताह पूर्व केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय प्रयोगणाला तथा मैटेरियल इंजीनियरिंग के एक दल की रिपोर्ट में बताया गया है कि आगरा के ताजमहल के मुख्य गुम्बद तथा अन्य जगहों पर पड़ी दरारों तथा मथुरा रिफाइ-नरी के चारों ओर स्थित ढलाई-घरों से निकलने वाल धुए से उत्पन्न प्रदूषण, सफेद पत्थरों पर काले घब्ये पडने, जिससे उसके सौन्दर्य व स्वरूप का नब्ट होना ताजमहल के साथ जडी देश की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इसकी अविलम्ब संरचनात्मक मरम्मत की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में बहुत लम्बे अर्से से आधिकारिक तौर पर कार्यवाही चल रही है। मरम्मत हेतु कुछ धन सरकार ने मंजूर भी कर दिया है, लेकिन पुरातत्व विभाग की ओर से कोई ठोस उपाय नहीं उठाये जा रहे हैं।

अतः सरकार से साग्रह अनुरोघ है कि ताजमहल की अनुपमेय गरिमा को बनाये रखने, धराणायी होने से बचाने तथा प्रदूषण के प्रभाव को कम करने या दूर करने के लिए तत्काल यथोचित कदम उठावे। यदि इसमें कोई लापर-वाही बरती गई तो ताज की सुन्दरता तो खत्म होगी ही, धराणायी होना भी कोई आण्चयं नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि विषव के श्रेष्ठ आर्किटेक्टर इंजीनियरिंग के विषेषज्ञों की एक कमेटी गठित कर इन दरारों को भरवाने का कार्य कराने में पहल करे।

(ii) Demand for Gwalior Region to be included in National Capital Region.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (Guna): Sir, the Government is introducing a bill during the current session of Parliament for setting up the National Capital Region Board which would include the representatives of Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. It may be recalled that Mr. Bhishma Narain Singh, the former Union Minister of Works and Housing had given an assurance that Madya Pradesh would be included in the NCR Board after it was set up.

The Gwalior region of Madhya Pladesh possesses the necessary infrastructure for inclusion in the NCR. It is quite near Delhi

**Introduced with the recommendation of the President.

^{*}Published in Gyazette of India Extraordinary. Part-11, Section 2, dated 24.7, 1984.